Newspaper Clips
December 13-14, 2015

December 13

Navodaya Times ND 13/12/2015 P-1

पीपीपी मोड पर खुलेंगे 3 नए आईआईटी

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर (ब्यूरो): मानव संसाधन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कैबिनेट से स्वीकृत छह नये आईआईटी में से तीन आईआईटी को पीपीपी मोड के तहत खोलने के लिए टाटा ग्रुप के साथ करार किया है। पीपीपी मोड के तहत टाटा ने आईआईटी रांची, आईआईटी नागपुर तथा आईआईटी पुणे को स्थापित करने का फैसला लिया है। समझौते के अनुसार पीपीपी के तहत खुलने वाले इन तीनों आईआईटी में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। इन आईआईटी को स्थापित करने में टाटा ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी तथा टाटा मोटर्स सहित कुल चार कंपनियां शामिल होंगी।

Hindustan Times ND 13/12/2015 P-1

IIMs to retain autonomy as govt waters down bill

HT EXCLUSIVE

Brajesh Kumar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Governing bodies of the Indian Institutes of Management (IIMs) may yet retain their autonomy as the controversial IIM bill has been redrafted to modify certain clauses that the boards argued would curtail their powers.

Doing away with contentious issues like seeking the Centre's approval on a range of functions, including increasing of the fee structures and changes in regulations, the new draft comes as a huge relief for the IIMs. The bill has now been listed for the ongoing session of Parliament.

The revised draft of the bill — which was circulated among different ministries for comments this week — also retains with the governing bodies the power to make crucial decisions on appointment of academic and administrative staff as well as manner of formation of academic departments.

The revisions were made to three key sections of the bill.

In section 36 (1) of the proposed bill, it stated that approval of the central government would be required for making rules on matters such as deciding remunerations of employees, the fee structure, and even construction of the new building blocks. The clause — 'with the approval of the central government' — has been scrapped.

Section 21 which gave the government power to issue any policy direction has also been scrapped.

Section 3 (k), which required any regulation made by the board to be approved by the government, has been modified to give the board the final say.

Both sections 3 (k) and 36 (1) drew severe criticism from the institutes who said the proposal would give sweeping powers to the government.

CONTINUED ON PAGE 8

from page one

IIMs to retain autonomy

"By virtue of these clauses, essentially the decision making power on virtually all issues would rest with the central government and the IIM boards would become recommendatory, not executive bodies," read a letter addressed to human resource development (HRD) minister Smriti Irani from IIM-Ahmedabad's board chairperson, AM Naik.

The letter was in response to the HRD ministry putting up the IIM bill in public domain, inviting comments from all stakeholders in June. IIM-Lucknow and IIM-Bangalore had earlier written similar letters asking the ministry to re-draft the bill in consultation with the IIMs.

The draft bill was initially conceived to give IIMs the power to award degrees instead of a post graduate diploma, thus making the management studies certificate recognizable abroad. It was also meant to give the IIMs flexibility to explore areas of study beyond management.

Following the uproar, the HRD ministry held several rounds of discussion with various IIM directors to address their concerns.

Amar Ujala ND 13/12/2015 P-16

सीबीएसई, राज्य के बोर्ड जारी कर सकते हैं फर्जी स्कूलों की सूची

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उच्च शिक्षण संस्थानों में स्कूलों के फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए दाखिला लेने के बढ़ते मामलों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब देशभर के शिक्षा बोर्डों को फर्जी स्कूलों के खिलाफ मुहिम तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई समेत राज्यों के शिक्षा बोर्डों को यूजीसी की तर्ज पर वेबसाइटों में फर्जी स्कूलों की सूची जारी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी प्रमाणपत्र देने वाले स्कूलों की पहचान कर उनको काली सूची में डाला जाए। फर्जी स्कूलों की बढ़ती संख्या की वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में हैं। साथ ही बढ़े उच्च शिक्षण संस्थानों में कई छात्र फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए दाखिला लेने में कामयाब हो रहे हैं। आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और कई

> फर्जी स्कूलों की बढ़ती संख्या की वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में

विश्वविद्यालयों की ओर से फर्जी प्रमाणपत्र से दाखिला लेने वाले छात्रों के मामले सामने आने के बाद मंत्रालय ने इस संबंध में तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अगर सीबीएसई समेत राज्य के शिक्षा बोर्ड भी अपनी वेबसाइटों पर फर्जी सूची देते हैं तो छात्र इन स्कूलों में दाखिला लेने से बचेंगे। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी स्कूलों की पहचान होने का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम जैसे बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में फर्जी स्कूलों के प्रमाणपत्र के जरिए दाखिला लेने वालों पर भी रोकथाम लग सकेगी।

December 14

Deccan Herald ND
14/12/2015 P-03

IIT asked to study air quality in Ghaziabad

GHAZIABAD: A residents' association in Ghaziabad has asked IIT-Delhi to conduct a detailed study of air polluting sources in this Delhi suburb, in view of the deteriorating air quality in the National Capital Region (NCR).

In a letter to IIT-Delhi, Col. Tejendra Pal Singh Tyagi (retd), president of the Apartment Owners Association Federation, said PM 1 (particulate matter of size less than 1 micro metre) has been found in the NCR.

A letter to the IIT from the member secretary of the Uttar Pradesh Pollution Control Board was written on May 11 to conduct a study, and the residents' association wrote to the institute to reiterate the UPPCB request.

Tyagi said the World Health Organisation (WHO) in a study in 2010 said Ghaziabad was among the top five places in India where the air was heavily polluted.

He said particulate matter was carcinogenic, and it gets deposited in the lower portion of the lung, thereby reducing lung capacity which was an irreversible problem.

He said the association had asked IIT-Delhi in July to conduct a study, but five months have passed, and there has been no response.

"We have been given to understand that diesel emissions, burning of biomass, polluting air discharge from factories, dust from the construction industry etc. contribute to PM 2.5 and PM 1. Therefore, you are requested to carry out a study and give us an idea of the approximate percentage contribution of these sources towards the formation of PM 2.5 and PM1," he said quoting from the letter.

He said there were over 300 polluting industries and about 100 brick kilns in Ghaziabad, and none of them conformed to the Pollution Control Board standards.

"Effluent treatment plants are said to be installed in all industries but we have our doubts if they are in operation round-the-clock," he said.

IANS

Hindustan ND 14/12/2015 P-14

आईआईटी की फीस जल्द बढ़ेगी

उत्तर प्रदेश

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

आईआईटी छात्रों पर जल्द ही बढ़ी हुई फीस का बोझ पड़ने वाला है। आईआईटी खर्चों को पूरा करने के लिए फीस बढ़ाएगा। इसकी तैयारी आईआईटी प्रशासन ने शुरू कर दी है। आने वाले समय में वेतन से लेकर होने वाले सभी खर्चों के संसाधन खुद आईआईटी जुटाएगा।

उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सिर्फ पेंशन का पैसा ही मिलेगा। बजट की समस्या को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आईआईटी काउंसिल ने यह सुझाव दिए है। इससे अब आईआईटी को पेंशन छोड़कर होने वाले सभी खर्चों की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। फिलहाल फैसला मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही लेना है। इसकी पुष्टि आईआईटी के नवनियुक्त चेयरमैन आरसी भार्गव और निदेशक इंद्रनील मन्ना ने की है। विजटर्स हॉस्टल में आईआईटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के बाद रविवार को पत्रकारों से बातचीत में चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि बजट की कमी गंभीर समस्या है।

आईआईटी और अन्य संस्थानों की संख्या बढ़ने से सभी को ज्यादा बजट मुहैया करा पाने में दिक्कत आ रही है। बजट एक चुनौती हो गया है। इसीलिए अब वेतन की व्यवस्था भी खुद आईआईटी को अपने संसाधन से ही करनी होगी।

बजट की कमी

- वेतन आदि खर्चों के लिए खुद संसाधन जुटाएगा आईआईटी
- खर्च का बोझ छात्रों पर पड़ेगा, एमएचआरडी सिर्फ पेंशन देगा

Business Standard Hindi ND 14.12.2015 P-07

पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेंगे नए आईआईटी

कोमल अमित गेरा और कल्पना पाठक

नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में कैम्पस प्लेसमेंट सीजन चौंकाने वाला साबित नहीं हो सकता है, जैसा कि उनके पुराने प्रतिस्पर्धियों ने दर्ज किया है, लेकिन यह पिछले साल के प्लेसमेंट के मुकाबले काफी बेहतर है।

ज्यादातर आईआईटी ने 75 प्रतिशत प्लेसमेंट कर लिया है और वे इस महीने या जनवरी 2016 के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे।

नए आईआईटी ने अपने कैम्पस प्लेसमेंट अक्टूबर में शुरू किए। आईआईटी संस्थानों का कहना है कि इस साल कैम्पस में आने वाली कंपनियों की संख्या अपेक्षाकृत पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। आईआईटी-रोपड़ में 25 कंपनियां अब तक कैम्पस का दौरा कर चुकी हैं जबकि पिछले साल यह संख्या 32 थी। संस्थान के प्लेसमेंट डिवीजन के एक अधिकारी ने कहा, 'हम इस साल अधिक संख्या में कंपनियों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कैम्पस प्लेसमेंट जनवरी-फरवरी के अंत तक जारी रहेगा।'

इस साल अब तक आईआईटी-रोपड़ आने वाली कंपनियों में एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, टैक्सस इंस्ट्रूमेंट्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, लार्सेन ऐंड टुब्रो, एक्सट्रिया मुख्य रूप से शामिल हैं।

आईआईटी-रोपड़ में लगभग 70 प्रतिशत छात्रों को पिछले

साल के मुकाबले अधिक औसत वेतन के साथ नौकरियों की पेशकश की गई। सर्वाधिक ऑफर अब तक 28 लाख रुपये का है, जो पिछले साल के सर्वाधिक ऑफर के समान ही है। अधिकारी ने कहा, 'सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े उद्यमों ने बड़ी तादाद में इस साल यहां पहली बार दौरा किया।'

आईआईटी रोपड़ में निदेशक एस के दास ने कहा, 'छात्रों की नियुक्तियों की संख्या के संदर्भ में हम पिछले साल के आंकड़े को पहले ही छू चुके हैं। बड़ी कंपनियों ने पुराने आईआईटी में प्रतिभाओं की खोज की है और हमें उन्हें जागरूक बनाने की जरूरत है। हमे बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़कर उन्हें दीर्घावधि आधार पर हमारे कैम्पस की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस साल हम बड़ी कंपनियों के साथ तालमेल बनाने की पहल अभी से शुरू करेंगे। छात्रों को साक्षात्कारों की चुनौती का सामना करने के लिहाज से अधिक विश्वस्त बनाने की कोशिश के तहत संस्थान द्वारा

ज्यादातर आईआईटी ने 75 फीसदी प्लेसमेंट कर लिया है और अगले महीने तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

बेहतर प्लेसमेंट के लिए पूर्व छात्रों के चयन में सुधार लाने की भी योजना बनाई गई है।' हिमाचल प्रदेश के आईआईटी-मंडी में कैम्पस साक्षात्कारों के लिए पंजीकृत 100 में से 65 छात्रों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। आईआईटी-मंडी में प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी ने कहा, 'पिछले साल हमारे यहां आने वाली कंपनियों की कुल संख्या 18 थी, लेकिन इस साल हमने अभी दूसरा राउंड भी पूरा नहीं किया है और 24 कंपनियां पहले ही दौरा कर चुकी हैं।'

आईआईटी-मंडी कैम्पस में दिलचस्पी दिखाने वाली प्रमुख कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और ईबे शामिल रही हैं। प्लेसमेंट प्रभारी ने कहा कि मंडी में छात्र स्टार्ट-अप उद्यमों के चयन को लेकर अधिक उत्साहित नहीं हैं और वे बड़े विकल्प तलाशना पसंद करते हैं।

निदेशक टिमोथी ए गोंजाल्वेस ने कहा कि वह उद्योग-शिक्षा सम्मेलनों के आयोजन के जरिये कॉरपोरेट सेक्टर के साथ तालमेल बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ सम्मेलन आयोजित किया और कई बड़े कॉरपोरेट घरानों ने कैम्पस का दौरा किया। हम अपने फैकल्टी के साथ शोध एवं विकास परियोजनाओं पर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपनी यात्राओं के दौरान वे यहां दिए जा रहे शैक्षिक मूल्यों की एक झलक पाएंगे। कैम्पस प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की संख्या में भी सुधार आया है। हम कंपनियों को निरंतर आधार पर यहां लाने की दिशा में काम करेंगे जिससे कि ये कंपनियां हमारे छात्रों को संपूर्ण रूप से करियर की राह मुहैया करा सकें।'

आईआईटी-पटना में प्लेसमेंट पिछले साल के मुकाबले इस बार बेहतर है। आईआईटी-पटना में प्लेसमेंट प्रभारी के सी रे ने कहा, 'गूगल और टैक्सस इंस्ट्रूमेंट ने हमारे छात्रों को अच्छे ऑफर दिए हैं। टैक्सस इंस्ट्रूमेंट द्वारा नियुक्ति हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हम इस महीने के अंत तक या जनवरी के शुरू तक प्लेसमेंट पूरा कर लेंगे।' सभी आईआईटी से औसत वेतन बढ़ा है। इस साल आईआईटी ने वेतन पैकेजों का खुलासा नहीं करने का निर्णय लिया है।

Asian Age ND 14/12/2015 P-13

IIT-K study on pollution to be released soon

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, DEC. 13

An IIT-Kanpur study that identified trucks and road dust as the biggest contributors to Delhi's polluted air is likely to be deliberated upon and officially released by the AAP government this week.

According to a senior Delhi government official, the report, titled "Source Apportionment Study of PM2.5 and PM10", has played a major role in the recent announcement of a series of anti-pollution measures by the Delhi government.

Sources in the AAP administration said that exhaustive findings of the report will be closely scrutinised during the deliberations as the report has for the first time identified separate patterns of pollution during summers and winters.

"The report has said that during winters the overall contribution of road dust comes down, which peaks during the dry summer months. Vehicular emissions make the city's air abysmally poor during the winter months," said a senior Delhi government official.

The report of the study, that was commissioned in 2013 and runs into over 300 pages, also recommends a switch to Euro VI emission compliant petrol and diesel. Incidentally, the city government announced its decision to adopt Euro VI by 2017 after receiving the report.

Euro IV fuels, currently in force in major cities, contain 50 parts per million (ppm) sulphur, while Euro VI stipulates 10 ppm sulphur. BS IV and BS VI are equivalents to the corresponding Euro fuels.

The lead investigator of the study, Professor Mukesh Sharma, would be asked to explain as to how his team had arrived at the conclusion and projected the figures.

Permits to 10,000 autos by Dec. end

The government will issue permits to 10,000 new autorickshaws by the end of this month. The government has already announced that it will add 6,000 additional buses to facilitate commuters during the 15-day trial period. Currently 80,000 autos ply in the city.

10L private cars to be off roads daily

There are over 19 lakh private four-wheelers registered in Delhi and nearly half of these will go off the roads with the implementation of AAP government's ambitious odd-even formula.

Amar Ujala ND 14/12/2015 P-06

आईआईटी में नौकरियों की बहार

अमर उजाला ब्यूरो

- बीते शुक्रवार तक मिले 620 जॉब ऑफर
- बीते साल से अच्छा प्लेसमेंट सेशन मान रहा संस्थान
- प्रतिदिन 15-20 कंपनियां आ रही हैं कैंपस

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में चल रहे प्लेसमेंट सेशन में घरेलू व विदेशी कंपनियों से भरपूर जॉब ऑफर मिल रहे हैं। इसका अंदाजा बीते शुक्रवार तक मिले लगभग 620 ऑफर छात्रों को प्राप्त हो चुके हैं। कैंपस में कंपनियों के पहुंचने में भी तेजी देखी जा रही है। बीते साल के मुकाबले में इस साल सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे मिले हैं।

आईआईटी दिल्ली में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल प्रमुख प्रो. शशि माथुर ने बताया बीते एक दिसंबर से शुरू हुए प्लेसमेंट सेशन में कंपनियों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इनमें काफी बड़ी कंपनियों के प्लेसमेंट ऑफर भी हैं। कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें चार से ज्यादा जॉब ऑफर मिले हैं। छात्रों को बीते साल औसतन नौ से दस लाख रुपये तक के ऑफर मिले थे, लेकिन इस बार सैलरी पैकेज बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट ने अब रफ्तार पकड़ी है और रोजाना 15-20 कंपनियां आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बीस से तीस लाख वाले सैलेरी पैकेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

वहीं कई ऑफर 60 लाख से एक करोड़ तक के भी हैं। अभी तक जो ऑफर प्राप्त हुए हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी से जुड़ी कंपनियों के ऑफर 40 फीसदी तक हैं। टेक्निकल कंपनियों से भी अच्छे ऑफर प्राप्त हो रहे हैं। प्रो. माथुर ने कहा कि 19 दिसंबर को पहले चरण का प्लेसमेंट सेशन खत्म होगा। उसके बाद ही सही रुप से कहा जा सकेगा कि पहले चरण में कितने छात्रों का प्लेसमेंट कितने सैलरी पैकेज पर हुआ।

Hindustan ND 14/12/2015 P-01

इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंक देख दाखिला ले सकेंगे

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

अगले सत्र से छात्र देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग को देखकर दाखिला ले सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने ऐलान किया है कि अगले साल अप्रैल से पहले 3500 इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग जारी कर दी जाएगी।

एआईसीटीई के चेयरमैन डॉ. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों को यह पता नहीं होता कि किस कॉलेज की गुणवत्ता कैसी है। चूंकि देश में 12 हजार से भी ज्यादा पेशेवर कॉलेज हैं। इन पर निगरानी कर पाना मुश्किल है। इसलिए कॉलेजों की रैंकिंग के जरिए पारदर्शिता लाई जाएगी।

उनके अनुसार, रैंकिंग जारी होने से जहां अच्छे कॉलेजों को ज्यादा से ज्यादा छात्र मिल पाएंगे, वहीं खराब गुणवत्ता के कॉलेजों को छात्र नहीं मिलेंगे।

सुविधा

- एआईसीटीई अगले साल अप्रैल तक रैंकिंग जारी करेगी
- इससे खराब गुणवत्ता वाले कॉलेजों को छात्र नहीं मिलेंगे

Smriti has a dig at two expat IIM directors

http://www.thehindu.com/news/national/smriti-has-a-dig-at-two-expat-iim-directors/article7981179.ece

As Prime Minister Narendra Modi continues to urge expats and the world to "Make in India", Union Human Resource Minister Smriti Irani recently struck a discordant note. In the course of an interview to a news channel, she singled out the directors of the Indian Institutes of Management of Ahmedabad and Bangalore for raising concern over the proposed IIM Bill, 2015.

And she pointed to the non-Indian status of the directors.

"Do you know why the directors of two IIMs, and not all, have expressed concern over the draft Bill on IIMs," Ms. Irani asked the interviewer. She went on to give the answer. "That is because, they are not Indians. Look at the beauty of our government in terms of tolerance. Even a foreign citizen can call our free press and wax eloquent about our government and our systems and tell us how our Parliament should legislate …"

Ms. Irani's comments on Ashish Nanda of the Ahmedabad institute and Sushil Vachani of the Bangalore one have created ripples at the institutes.

Mr. Nanda worked at Harvard and Mr. Vachani at Boston University. Both were chosen by a select committee of the societies of the two IIMs. Both left behind lucrative careers and came to India to head institutes of excellence, something Prime Minister Narendra Modi wanted them to do.

What has caused concern in management and academic circles is what they call a loaded attack on the directors for criticising the Bill. Mr. Nanda in particular has been quite outspoken in flagging issues of autonomy of the institutes. The IIMs pointed out that some provisions in the Bill, as reported in *The Hindu*, would seriously impact the autonomy of the institutes. Professor Anil Gupta of the IIM-Ahmedabad said: "It is the academic faculty of the IIMs which had raised concerns. It is not about individuals."

The Hindu sent a mail to the directors who politely refused to comment. A mail sent to the HRD Ministry for the Minister's comments did not elicit any response, though it was acknowledged.

Ms. Irani's comments come after her Ministry's attempts to iron out differences over the Bill following concerns raised over the erosion of autonomy of the IIMs.

Sources point to three implications of Ms. Irani's observations. First, the impact on free speech, and what they see as the government's attempt to silence critics. As a senior academic faculty member said: "Had it not been for the criticism, the government would not have gone back to the drawing board to redraft the Bill." The second is what is the point of inviting the cream of academics from abroad to raise the standards of the IIMs, if they are attacked by Ministers themselves?

The third, the Bill makes its objective clear: to have management institutions of national importance with a view to empowering them to attain standards of global excellence in management, management research and allied areas of knowledge.

The Ministry has invited public comments on the Bill. Parliament is likely to debate the matter soon.

New Education Policy followed the spirit of cooperative federalism: Smriti Irani

http://indiatoday.intoday.in/education/story/new-education-policy-smriti-irani/1/545182.html

On December 11, the Union Human Resource Development Minister, Smriti Irani said that the new education policy which is under consideration will be cooperative federalist in spirit. According to a report in Indo-Asian News Service (IANS), Smriti Irani said, "The process of consultation on new education policy has followed the spirit of cooperative federalism."

When asked about the introduction of Bhagavad Gita in schools, Smriti Irani added, "The first school for kids is their home with parents as teachers. It's not fair to say only school has a role in child's development." Replying to a question to rising 'intolerance' in the country, she said, "The individuals returning awards never did the same when they were examples of violence when Congress was in power."

The Government of India would like to bring out a National Education Policy to meet the changing dynamics of the population's requirement with regards to quality education, innovation and research.